



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 1992/ज्येष्ठ 4, 1914

No. 311]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 1992/JYAISTHA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है किससे इक यह अलग संकालन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रस्तावना-कार बोर्ड

प्रधिकूलता

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

प्राय-कर

का. ना. 357 (प्र).—केन्द्रीय प्रस्तावना-कार बोर्ड प्राय-कर प्रविनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, प्रथमतः—

1. (1) इन नियमों का संभिल नाम प्राय-कर (दसवा संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये 1 मर्च, 1991 से लागू समझे जाएंगे।

2. प्राय-कर नियम, 1962 में, नियम 6के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, प्रथमतः—

“6क. धारा 43प के उपर्युक्त प्रत्येक लोक वित्तीय भूस्था, मन्त्रालय बैंक, राज्य वित्तीय नियम और राज्य औद्योगिक वित्तियान नियम की दशा

में, वहाँ लागू होंगे जहाँ व्याज के रूप में उत्तरी आय, डूबन और गंकास्पद झूणों के निम्नलिखित प्रवणताएँ संबंध में हैं, प्रथमतः—

(क) (i) अक्षम या अटके हुए ज्ञान प्रथमतः जहाँ उपर्युक्त (ii) में विनिविष्ट प्रकृति की आनियमिताओं, उधार लेने वार्ताओं के लेखाओं में छह मास और उससे अधिक की अवधि के लिए व्यात में आती है और जहाँ लेखाओं के विनियमन की न्यूनतम संभावनाएँ महीं हैं या जहाँ लेखाओं व्यष्टि ऐसे लेखाओं की बाबत निम्न प्रकार की रूपान्तर की ओप्शनार्क लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जैसे —

1. व्यीमे या नग्न्य आवल के परिणामस्वरूप कारबाह में आभासी असरोद्ध;

2. भ्रायावान के लिए लगातार अनुरोध करना या लेखा में नियमों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना चैक जारी करना;

3. क्रप किए गए विल या मिलिकाटे के भूगतान तीन मास और उससे अधिक के लिए अतिशोष्य रहते हैं या ऐसे विलों की वसूली में उधार लेने वाले कठिनाइया उत्पन्न करता हैं;

4. ऐसे सावधि झूणों, फिलों की दशा में जो छह मास या उससे अधिक की अवधि से अतिशोष्य हैं;

5. देंक द्वारा अपेक्षित धैर्यासिक या अर्द्धधैर्यासिक प्रबालन विवरण या स्टाक विवरण अथवा तुलनपत्र और अन्य जानकारी देने में उद्धार लेने वाले द्वारा अस्पष्ट विवरण;

6. निरीक्षण के बीच ग्रन्थालेखित स्टाक का धैर्या संचलन या अवरोध;

7. कारबार के निरीक्षण या निलम्बन ग्राथवा बंद करने के बौद्धन अश्वलांकित अतिवाक्यालापो वा इस या नमन्य स्तर;

8. मुख्य आवश्यकताओं जैसे वस्तावजों का निष्पादन, जब अपेक्षित है, अंतिरिक्त प्रतिभूति देने का अनुपालन करने में लगातार विलम्ब या ऐसी घटेकारों का अनुपालन न करना;

9. महयोगी एककों को निधियों का अपयोजन या कारबार से प्राप्त पूँजी आवश्यियों का अर्जन अथवा धार लेने वाले द्वारा अकिञ्चित रूप से बड़ी रकम निकाला जाना;

10. परियोजना के कार्यक्रम से आशयित अनासंजन जिसके कारण लागत में साराजान बढ़ि होती है और अतिरिक्त मावधिक त्रित की अपेक्षा होती है;

11. समापन पर दबाव जिसके कारण कमेकारों की मजदूरी या कानूनी जोखियों अथवा कार्यालय और कारबार के परिसर के किराये का संदाय न करना;

12. चालू आरियों से अधिक चालू दायित्व;

13. उधार लेने वालों के लेब्र/ परोक्षकों द्वारा अवलोकित कोई भारी अनिवार्यता जिसका मुद्दार किया जाना चाही है;

14. एकक के दिनीय विवरणों द्वारा परकटित प्रायमिक कमजोरी उदाहरणार्थ एक साल के बाव लगातार रोकड़ हानि।

(ii) उधार लेने वालों के लेब्रों में उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट अनिवार्यताएं निम्नलिखित हैं, --

1. जहां लेकारों से, अस्त्यायी अवधि के लिये आहरण शक्ति, भंजूर की गई सीमा, स अधिक अध्यादान;

2. साथाधि हानि की बाबत किसी लाह मास से अध्यून के लिये अविशेष्य है या प्रत्ययत्व के घटीय आयात विलों अथवा आपराधित संदाय के अर्धान किसी तीन मास से अध्यून के लिये अविशेष्य रहती है;

3. क्य किये गये विलों में कुल बकाया का 10% से 15% से अधिक विल या उधार लेने वाले के मिलिकाटे लेब्र तीन मास से अध्यून अवधि के लिये संदाय के लिये अविशेष्य हैं और असंदर्भ विलों के मंदिर में प्रतिक्रिय तुरन्त नहीं हो रहा है।

(अ) वापस लिये गये अग्रिम, अर्थात् जहां प्रतिवाय अतिशंकास्पद हो और एकक को पुनःप्रबन्धित करना उचित नहीं समझा जाता हो और अग्रिमों को वापस लेने के लिये निर्णय ले लिया गया हो।

(ग) वाद फाइल किये गये लेब्रा अर्थात् जहां विधिक कारंवाह या बसूली कारंवाहिया प्राप्त कर दी गई है और अग्रिम की बसूली के लिये वाद लम्बित है।

(घ) छिकीगत क्षण, अर्थात् जहां वाद फाइल कर दिये गये हैं और छिकी प्राप्त कर ली गई है तथा ऐसी छिकी निष्पादन के लिये सम्मित है।

(ङ) उनके अणों की बसूली, प्रतिभूति की कीमत में हुई कमी, प्रतिभूतियों को प्रवत्त करने और निर्माणित करने में कठिनाई, या उधार लेने वालों की बैंक की शोध रकमों को भागतः या पूर्णतः प्रतिवाय करने में अवशता

प्रयत्ना भनिच्छा के कारण नंकास्वद हो गई है और ऐसे अणों को पूर्णगापी खंड (क) से (घ) गे सम्मिलित नहीं किया जाता है।"

[न. 9029/का.सं. 142/29/9-टीपीएल(भाग)]
अधिकारी प्रमाण, निवेशक (टीपीएल-1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Board of Direct Taxes

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 1992

INCOME-TAX

S.O. 357(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Tenth Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall be deemed to come into force the 1st day of April, 1991.

2. In the Income-tax Rules, 1962,

after rule 6E, the following rule shall be inserted, namely :—

"6EA. The provisions of section 43D shall apply in the case of every public financial institution, scheduled bank, State financial corporation and State industrial investment corporation where its income by way of interest pertains to the following categories of bad and doubtful debts, namely :—

(a)(i) Non-viable or sticky advances, [i.e., where irregularities of the nature specified in sub-clause (ii) are noticed in the accounts of the borrowers for a period of six months and more and there are no minimum prospects of regularisation of accounts, or where the accounts or information in relation to such accounts reflect usual signs of sickness, such as,—

1. apparent stagnation in the business as a result of the slow or negligible turnover ;

2. frequent requests for over-drawing or issue of cheques without ensuring availability of funds in the account;

3. bills purchased or discounted remain overdue for 3 months and more or the recovery of such bills from the borrower poses difficulties ;

4. in the case of term-loans, instalments which are overdue for 6 months or more;

5. unexplained delays by the borrower in submission of quarterly or half-yearly operating statements or stock statements or balance sheets and other information required by the bank;

6. slow movement or stagnation of stocks observed during inspections ;

7. low or negligible level of activity observed during inspections or suspension or closure of the business;

8. persistent delay in compliance with vital requirements like execution of documents, producing additional security when required or non-compliance with such requirements;

9. diversion of funds to sister units or acquiring capital assets not relevant to the business or large personal withdrawals by the borrowers;

10. international non-adherence to project schedules leading to substantial cost escalations and requirement of additional term-finance.

11. the pressure on the liquidity leading to non-payment of wages to workers or statutory dues or rents of office and factory premises;

12. the current liabilities exceeding current assets;

13. any grave irregularities observed by the auditors of the borrowers which remain to be rectified;

14. basic weakness revealed by the financial statements of the unit, for example, continued cash loss beyond one year.

(ii) The irregularities referred to in sub-clause (i) in the accounts of the borrowers are,—

1. where the accounts are over-drawn beyond the drawing power or the sanctioned limit, for a temporary period;
2. installments in respect of term loss are overdue for less than 6 months or import bills under letters of credit or installments under deferred payment carried are over due for less than 3 months;
3. bills not exceeding 10 per cent to 15 per cent of the total outstanding in the bills purchased or discounted account of the borrower are overdue for payment for a period of less than 3 months and refund in respect of unpaid bills is not forthcoming immediately.]

(b) Advances recalled, i.e., where the repayment is highly doubtful and revival of the unit is not considered worthwhile and a decision has been taken to recall the advances.

(c) suit-filed accounts, i.e., where legal action or recovery proceedings have been initiated and suits are pending for recovery of advances.

(d) decreed debts, i.e., where suits have been filed and decree obtained and such decree is pending for execution.

(e) Debts recoverability whereof has become doubtful on account of shortfalls in value of security, difficulty in enforcing and realising the securities, or inability or unwillingness of the borrower to repay the banks dues—partly or wholly and such debts have not been included in preceding clauses (a) to (d)."

[No. 9029/F. No. 142/29/91-TPL (Part)]
AKHILESH PRASAD, Director (TPL-I)

